जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 125 प्रभात चूरू, रविवार 1 सितम्बर, 2024 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

कमला हैरिस ने ट्रम्प पर चार पॉइन्ट्स की लीड स्थापित की

रॉयटर द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार, राष्ट्रपति पद पर 45 प्रतिशत लोग कमला हैरिस को देखना चाहते हैं तथा 41 प्रतिशत ट्रम्प को

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर बढ़त ले ली है। यह जानकारी मिली रॉयटर्स/इप्सॉस पोल के सप्ताहांत में नतीजों से। नतीजों के अनुसार, कमला को 45 प्रतिशत डॉनल्ड ट्रम्प को 41 प्रतिशत वोट मिले हैं। आठ दिन चला यह सर्वे शुक्रवार को ही खत्म हुआ है। इसके अनुसार, जुलाई के अंत में हैरिस को मिली एक पॉइन्ट की बढ़त के मुकाबले यह उल्लेखनीय बढ़त है। हैरिस को जो बढ़त मिल रही है उसके लिए महिलाओं और हिस्पैनिक मतदाताओं का बढ़ता समर्थन है। इन दोनों समूहों में उनकी लोकप्रियता ट्रम्प से 13 प्रतिशत अधिक है। दोनों समूहों में उनकी लोकप्रियता 49 से 36 प्रतिशत है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महिलाओं में उनकी लोकप्रियता 9 प्रतिशत तक और हिस्पैनिक मतदाताओं में 6 प्रतिशत तक बढ़ी है, हालांकि श्वेत मतदाताओं और पुरूषों में ट्रम्प अभी भी आगे हैं, पर कॉलेज डिग्री रहित युवाओं में उनकी लोकप्रियता 7 पॉइन्ट घटी है।

- जुलाई के अन्त में कराये गये सर्वे में, कमला हैरिस की ''लीड'' केवल एक प्रतिशत थी।
- हैरिस की लीड में इतनी भारी बढ़ोतरी होने का कारण है, कमला हैरिस की लोकप्रियता में महिलाओं और हिस्पैनिक लोगों का समर्थन 13 प्रतिशत बढ़ा है, गत महीने के सर्वे रिज़ल्ट की तुलना में।
- इस सर्वे में अमेरिका के 4253 नागरिकों से तथा चुनाव में वोट देने के लिये रजिस्टर्ड 3562 अमेरिकी नागरिकों से यह सवाल पूछकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको देंगे, उनकी राय जानी गयी थी।

जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से बाहर होने के बाद से हालात में काफी परिवर्तन आया है। बाइडन के पीछे हटने के बाद हैरिस को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रमुख राज्यों के चुनावों में काफी बढ़त मिली है। विस्कॉन्सिन, पैनसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिज़ोना, नॉर्थ कैरोलाइना, मिशीगन और नेवाडा जैसे राज्यों में जहाँ कड़ा मुकाबला है वहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स में ट्रम्प को हैरिस पर मामूली सी बढ़त प्राप्त है। लेकिन ब्लूमबर्ग न्यूज़/मॉर्निंग कंसल्ट पोल से पता चलता है कि यहां पर तो हैरिस आगे चल रही हैं या ट्रम्प के बराबर हैं।

रिपब्लिकन नीतिकार मैट वॉल्किंग ने माना कि हैरिस से ट्रम्प को कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प के लिए महत्वपूर्ण है कि वोटर्स का समर्थन बनाए रखने के लिए व चुनाव प्रचार रणनीति पर फोकस करें।

जब से हैरिस को डैमोक्रैटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है तब से वे जॉर्जिया जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में सक्रिय चुनाव अभियान चला रही है ताकि उनका जनाधार मजबूत हो जाए।

हैरिस के लिए जनता में उत्साह साफ नज़र आ रहा है। रॉयटर्स/इप्सॉस सर्वे में शामिल 73 प्रतिशत डैमोक्रैटिक वोटर्स ने कहा कि नवम्बर में होने वाली वोटिंग के प्रति उनका उत्साह बढ़ गया है। प्रगतिवादी सोच के मतदाताओं में ट्रम्प की तुलना में हैरिस का असर ज्यादा है। हैरिस के 52 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा कि उनका लक्ष्य ट्रम्प का विरोध करने से कहीं ज्यादा हैरिस को मजबूत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साइबर फ्रॉड केस में पुलिस को अल्टीमेटम

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के ढाई साल पुराने मामले में कार्रवाई नहीं होने और इन केसों में हो रही बढोतरी को गंभीर माना है। अदालत ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा कि जब सी.जे.आई. के साथ ही साइबर फ्रॉड हो चुका है तो फिर पुलिस ऐसे मामलों में इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है।

- राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा, सी.जे.आई. तक के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है फिर भी पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है। कोर्ट ने 60 लाख रूपए के साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस को 30 दिन में कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया।

अदालत ने पुलिस को कहा है कि यदि 30 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर को डी.जी.पी. व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश 60 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में राकेश तोतुका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामला वर्ष 2022 से चल रहा है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी के स्वघोषित हनुमान संकट में हैं बिहार में?

क्या भाजपा, अपने एन.डी.ए. गठबंधन के साथी चिराग पासवान के पर कुतरना चाहती है?

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वघोषित हनुमान संकट में दिखाई दे रहे हैं।

राकेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति, जो उड़ती खबरों के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता हैं, ने एक याचिका लगाई है तथा चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। उन्होंने तीन गंभीर आरोप लगाये हैं- पहली, वे (चिराग) एक दुष्कर्म केस में द्वितीय आरोपी हैं, दूसरी, उन्होंने अपने चुनाव-शपथपत्र में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के बारे में झूठ बोला था; तथा तीसरी, उन्होंने बिहार के खगरिया जिले की अपनी सम्पत्ति के स्वामित्व की बात छुपाई थी। बिहार भाजपा के मीडिया प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण देते हुये कहा है कि याचिकाकर्ता का भाजपा से कोई सम्बंध नहीं है। लेकिन चिराग की पार्टी और भाजपा के बीच पैदा हो रहे इस संकट का परिदृश्य काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

- भाजपा के एक तथाकथित कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायी है कि चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने से पहले जो शपथ पत्र के माध्यम से जानकारियाँ प्रस्तुत की हैं, झूठ हैं, असत्य हैं।
- साथ ही भाजपा विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया कि चिराग पासवान की पार्टी के पाँच निर्वाचित सांसदों में से तीन ''जॉइन'' करने को तैयार हैं।
- इस घटनाक्रम के बीच चिराग पासवान के मुख्य प्रतिद्वंदी तथा चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस अचानक सक्रिय हुए और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मिले तथा शाह को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।
- क्या ये संकेत है कि भाजपा खुश नहीं कि चिराग पासवान एन.डी.ए. के खिलाफ सबसे अधिक बोलने वाले नेता के रूप उभर रहे हैं। अतः उन्हें जमीन पर उतारना जरूरी है।

एन.डी.ए. के सभी घटक दलों में, चिराग केन्द्र सरकार के हाल ही के नीतिगत निर्णयों के सर्वाधिक मुखर विरोधी रहे हैं। इन नीतियों में, वक्फ बिल में प्रस्तावित संशोधन, तथा नौकरशाही में सीधी एवं स्वैच्छिक भर्ती करने की योजना, जो अब वापस ले ली गई है, प्रमुख रुप से शामिल हैं। चिराग विपक्ष द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना की माँग के समर्थन में भी आ गये थे। इन सभी मुद्दों पर सरकार द्वारा अपने कदम पीछे हटा लेने के साथ ही, भाजपा में एक सोच यह भी बनी है कि चिराग अपने कद से कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं तथा उन्हें रोकने की जरुरत है।

हाल ही के दिनों में, बिहार के एन.डी.ए. पार्टनरों में बड़ी तेजी से कुछ हलचल होती दिखाई दी है। चिराग के चाचा तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस गुमनामी से एकाएक ही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

8 सितम्बर को 3 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी

विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले विदेश दौरे में राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। वे 8 से 10 सितम्बर तक अमेरिका में रहेंगे। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने कहा कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तब से उनके पास बहुत सारे आवेदन आ रहे है, जिनमें राहुल गांधी से मिलने का आग्रह किया गया है।

गांधी 8 सितम्बर को डलास, टैक्सस में रहेंगे तथा 9 व 10 सितम्बर को वॉशिंगटन डी.सी. में रहेंगे।

इस दौरान वे शिक्षाविदों, पत्रकारों, थिंक टैंक्स के प्रतिनिधियों टैक्नोक्रेट्स, व्यवसायियों व भारतीय मूल के अन्य लोगों व स्थानीय लोगों से मिलेंगे।

इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस जिसकी उपस्थिति 32 देशों में है, के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल की यात्रा की औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं, मेरे पास भारतीय मूल के लोगों, इंटरनैशनल मीडिया व अन्य नेताओं की तरफ से आवेदनों की भरमार लगी है। वे सभी राहुल से बात करना चाहते हैं। अब राहुल संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका आ रहे हैं।

- इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि जब से राहुल विपक्ष के नेता बने हैं, उनसे मिलने के लिए हमारे पास अनगिनत आवेदन आए हैं।
- पित्रोदा ने कहा कि तीन दिन के प्रवास में राहुल गांधी शिक्षाविदों, पत्रकारों, उद्योगपतियों, भारतीय मूल के लोगों व छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे तथा विभिन्न मसलों पर चर्चा करेंगे।

डलास में गांधी युनिवर्सिटी ऑफ टैक्सस के छात्रों, शिक्षाविदों व अन्य लोगों से वार्ता करेंगे।

कुछ टैक्नाफ्रेटस से भी चर्चा होगी और रात्रि भोज पर इलास के नेताओं से मिलेंगे।

वॉशिंगटन में वे थिंक टैक और नैशनल प्रैस क्लब व अन्य लोगों से मिलेंगे।

पित्रोदा ने बताया कि कई लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। लोगों को उन राज्यों में भी काफी रूचि है जहाँ कांग्रेस का शासन है। खासकर बैंगलुरु, हैदराबाद और उम्मीद है कि हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे क्योंकि लोगों को पुणे, मुम्बई व गुड़गांव में भी दिलचस्पी है।

ये देश के बिज़नैस शहर हैं जहाँ टैक्नॉलजी पर काफी फोकस है।

पित्रोदा ने कहा कि हम राहुल गांधी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यू.डी.एच. सचिव और डी.एल.बी. निदेशक को अवमानना नोटिस

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिप्टी टाउन प्लानर के निलंबन से जुडे मामले में करीब एक साल पुराने अदालती आदेश की पालन नहीं करने पर प्रमुख यू.डी.एच. सचिव टी.रविकांत व डी.एल.बी. निदेशक सुरेश ओला को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश राजपाल चौधरी की अवमानना याचिका पर दिया।

- हाई कोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।

याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि याचिकाकर्ता डी.एल.बी. में डिप्टी टाउन प्लानर के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उन्हें बिना नाम व पते वाली झूठी शिकायत पर 13 फरवरी 2023 को चार्जशीट देते हुए निलंबित कर दिया। चार्जशीट भी उस अफसर ने दी जिसे देने का अधिकार नहीं था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तिथि एक अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर की

कांग्रेस और आप का कहना है, यह संकेत है कि हरियाणा में भाजपा हतोत्साहित है और अभी से अपनी गलती स्वीकार कर रही है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। भाजपा की इच्छा की सुस्पष्ट अनुपालना में, भारत के चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदान-तिथि 1 अक्टूबर से खिसका कर 5 अक्टूबर कर दी।

जम्मू-कश्मीर के तृतीय चरण की मतदान तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वह 1 अक्टूबर ही बनी हुई है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित होंगे।

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा, ''चुनाव तिथि निर्धारण के बाद, राष्ट्रीय राजनैतिक दलों, प्रांतीय राजनैतिक दलों, तथा अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के आग्रह-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें कहा गया था कि सदियों पुराने असोज अमावस्या त्योहार पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिये विश्नोई समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा से राजस्थान जायेंगे।''

- चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का कारण है कि, ऑल इंडिया विश्नोई महासभा का ज्ञापन मिला था कि सदियों पुराने त्योहार आसोज अमावस्या पर हरियाणा के विश्नोई राजस्थान जाते हैं, ऐसे में उनका वोट डालना संभव नहीं हो पाएगा।
- चुनाव आयोग ने एक और कारण यह बताया कि, सप्ताहांत के साथ कई छुट्टियाँ होने के कारण लोग प्रायः घूमने निकल जाते हैं।
- चुनाव आयोग ने कहा, इन कारणों से मतदान प्रतिशत में भारी कमी आ जाती इसलिए हरियाणा के चुनाव आगे सरकाए गए हैं।

ई.सी. की अधिसूचना में कहा गया है, ''पूर्व निर्धारित तिथि पर मतदान होने से बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते तथा हरियाणा विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती।''

24 अगस्त को हरियाणा भाजपा की 'राज्य चुनाव प्रबन्धन समिति' के सदस्य वरिन्दर गर्ग ने कहा था, ''हमने यह तर्क दिया है कि विधानसभा चुनाव की तिथि 1 अक्टूबर (मंगलवार) के पहले सप्ताहान्त अवकाश तथा बाद में भी छुट्टियाँ हैं, जिससे मतदान - प्रतिशतता प्रभावित हो सकती है क्योंकि लोग लम्बे सप्ताहान्त अवकाशों पर प्रायः छुट्टियाँ ले लेते हैं।''

विपक्षी कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी ने इस कार्यवाही की आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता भूपिन्दर सिंह हूडा ने भाजपा पर प्रहार करते हुये कहा है कि पार्टी का रुख बताता है कि उसने पराजय पहले ही स्वीकार कर ली है। मीडिया ने इस वरिष्ठ नेता को यह कहते हुये उद्धृत किया है, ''मतदान ई.सी. द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही होने चाहिये।.....हरियाणा की जनता भाजपा सरकार को एक दिन भी सत्ता में देखना नहीं चाहती।''

आप की हरियाणा इकाई ने कहा कि चुनाव होने से पहले ही, सत्तारुढ़ भाजपा ने बहाने तलाश करना शुरु कर दिया था क्योंकि उसने चुनाव में आसन्न पराजय भाँप ली है।

जहाँ भाजपा हरियाणा में लगातार तीसरे कार्यकाल पर नजरें जमाये हुये हैं, वहीं कांग्रेस सत्तारुढ़ दल को सत्ता सेहटा देने की आशा सँजोये हुये है।

चेन्नई के हॉस्टल में रेड, 32 छात्र हिरासत में

चेन्नई, 31 अगस्त। तमिलनाडु में पुलिस ने शनिवार को उन हॉस्टल्स में छापेमारी की, जहां चेन्नई के पास पोथेरी में प्राइवेट कॉलेज के छात्र रहते हैं। इस दौरान एक महिला समेत 32 कॉलेज स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। इन्हें एक निजी मैरिज हॉल में रखा गया है और अलग-अलग से पूछताछ की जा रही है। तांबरम नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबलों ने आज यह रेड मारी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। साथ ही भांग चॉकलेट, भांग का तेल और भांग से संबंधित दूसरी चीजें जब्त की गईं। पुलिस की ओर से

- पुलिस ने हॉस्टल में अचानक रेड डालकर छात्रों के कमरों से भारी मात्रा में गांजा, भांग का तेल व नशीली ड्रग्स इत्यादि बरामद की हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति में कानूनी मायाजाल में फंसी सरकार'

अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर हुई इस नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से और जल्दबाजी में यह नियुक्ति की

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में 2019 में नामांकित अधिवक्ता, पद्मेश मिश्रा, को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पैरवी के लिये अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए.ए.जी.) घोषित किये जाने के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता-अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने याचिका में मुख्य तौर पर इस मुद्दे पर जोर दिया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 की वाद नीति में संशोधन किया और एक नया 'क्लॉज़ 14.8' को जोड़कर स्वयं को बेलगाम शक्तियां देने का प्रावधान जोड़ा जिसके तहत वे किसी भी अधिवक्ता, के अनुभव को आंकने के बाद, उसे अतिरिक्त महाधिवक्ता, महाधिवक्ता या किसी भी सरकारी वकील के पद पर नियुक्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 की वाद नीति में कोई और संशोधन नहीं किया जबकि इसी वाद नीति में 'क्लॉज़ 14.4' के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिये अधिवक्ता के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

- याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ''राज्य सरकार ने वर्ष 2018 की वाद नीति में संशोधन किया और एक नया ''क्लॉज़ 14.8'' जोड़ा और स्वयं को बेलगाम शक्तियां दीं ताकि वो किसी भी अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति दे सके।
- परंतु उसने इसी वाद नीति के 'क्लॉज़ 14.4' में संशोधन नहीं किया, जिसके अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिये अधिवक्ता के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिये।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता को नियुक्त करने से पूर्व राज्य के महाधिवक्ता से ही सलाह नहीं ली गई थी, जो कि वाद नीति के 'क्लॉज़ 14.2' के अनुसार अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता समदड़िया ने इस मामले में आवेदन दायर कर यह भी गुहार की थी कि पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के आदेश पर तुरंत प्रभाव से अंतरिम रोक भी लगाई जाये। इस मामले की पहली सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिल उपमन ने राज्य सरकार तथा अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को नोटिस जारी किये और कहा कि याचिकाकर्ता अगली सुनवाई पर नियुक्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के अपने आवेदन पर जिरह जारी रख सकते हैं।

इस मामले में दायर याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने 23 अगस्त 2024 को वाद नीति में एक संशोधन किया जिसके तहत उसने स्वयं को बेलगाम शक्तियां देने का प्रावधान जोड़ा जिससे वह किसी भी अधिवक्ता को मनमाने तरीके से अतिरिक्त महाधिवक्ता घोषित कर सकती है। याचिका में यह भी बताया गया है कि 23 अगस्त को ही राज्य सरकार ने पद्मेश मिश्रा को अतिरिक्त महाधिवक्ता घोषित करने का आदेश भी पारित किया। याचिकाकर्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई

नयी दिल्ली 31 अगस्त (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए सरकार से युवाओं के खुशहाल भविष्य के लिए विकासोन्मुखी योजना बनाने का आग्रह किया है।

- राहुल गांधी ने कहा कि बीते एक दशक में भारत में आत्महत्या के मामले दोगुने हो गये हैं। बीते दस सालों में 13 हजार 44 युवाओं ने आत्महत्या की है तथा उससे पहले के दस वर्षों में यह आंकड़ा 6,654 ही था।

गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)